

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र० क० 358-तीन/2014 विरुद्ध आदेश दिनांक
18-11-2014 पारित आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक
121/12-13 अपील.

चन्द्रा बेवा पत्नी अन्तू आदिवासी
निवासी ग्राम कांकर, तह० व जिला
शिवपुरी, म०प्र०

— आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
शिवपुरी, म०प्र०

— अनावेदक

श्री एस० पी० धाकड़, अभिभाषक — आवेदक
श्री डी० के० शुक्ला, पैनल अभिभाषक— अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 1-5-2014 को पारित)

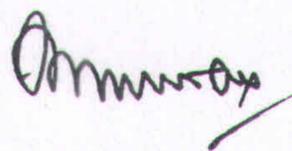
यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
(जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त,
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 121/2012-13 अपील में पारित
आदेश दिनांक 18-11-2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।



2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका चन्द्रा ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम करई एहमदपुर स्थित भूमि सर्वे0 नं0 67 रकबा 0.56 हे. के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदनपत्र कलेक्टर जिला शिवुपरी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 19-9-12 द्वारा खारिज किया। इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, ग्वालियर संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 18-11-13 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है कि विधिवत जाँच उपरान्त प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण किया जाय। इस आदेश के विरुद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

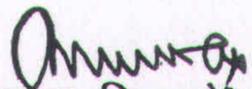
3/ मैंने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदिका के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका द्वारा पंजीयत विक्रयपत्र द्वारा खरीदी गयी है। इस भूमि के अलावा आवेदिका के सहभूमिस्वामी स्वत्व में ग्राम कांकर में स्थित है। आवेदिका की भूमि उबड़-खावड़ है एवं ग्राम कांकर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, इसलिये आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय कर ग्राम कांकर में स्थित भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सिंचित करना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदिका के आवेदनपत्र पर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं कर विक्रय अनुमति प्रदान नहीं करने में भूल की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक का तर्क है कि विद्वान आयुक्त ने आवेदिका के आवेदनपत्र पर विधिवत जाँच कर निराकरण करने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।



5/ कलेक्टर के अभिलेख से आवेदिका द्वारा दिनांक 3-9-12 को विक्रय अनुमति हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करना और कलेक्टर द्वारा इस आवेदनपत्र पर जाँच कर तहसीलदार का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किये बिना ही अपने आदेश दिनांक 19-9-12 द्वारा विक्रय अनुमति आवेदनपत्र खारिज किया गया है। विद्वान आयुक्त ने अपने आदेश में यही निष्कर्ष निकाला है कि आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जाँच तहसीलदार द्वारा करायी जाकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना चाहिये था या पीठासीन अधिकारी उचित समझे तो स्वयं मामले की जाँच कर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिये था। विद्वान आयुक्त द्वारा निकाला गया उक्त निष्कर्ष विधि अनुकूल है और आयुक्त द्वारा प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनांक 18-11-2013 यथावत रखा जाता है।


(अशोक शिवहरे)

सदस्य,

राजस्व मण्डल, म0प्र0